राजस्थान उच्च न्यायालय , जोधपुर

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 4842/2007

सोजी राम मीना

----याचिकाकर्ता

बनाम

राज्य और अन्य

---प्रतिवादी

याचिकाकर्ता(ओं) के लिए: श्री अचरज सलूजा।
प्रतिवादी(ओं) के लिए:

माननीय न्यायमूर्ति अरुण मोंगा

आदेश(मौखिक)

रिपोर्ट योग्य

20/03/2024

1. इस याचिका में अन्य बातों के साथ-साथ प्रतिवादियों को याचिकाकर्ता को जूनियर इंस्ट्रक्टर (विद्युतकर) के पद पर कार्यभार ग्रहण कराने का निर्देश देने की मांग की गई है।

2. मामले के संक्षिप्त तथ्य, अनावश्यक विवरणों से अलग यह हैं कि प्रतिवादी संख्या 2 ने 5 फरवरी, 2007 को जूनियर इंस्ट्रक्टर के पद के लिए विज्ञापन दिया था, जिसमें विभिन्न औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में बैकलॉग के कारण कई रिक्तियां थीं। याचिकाकर्ता ने रोजगार सूचना नियमों का पालन करते हुए छह बैकलॉग पदों के विरुद्ध इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में पद के लिए आवेदन किया था। लिखित परीक्षा में बैठने की अनुमति मिलने के बाद,

याचिकाकर्ता ने लिखित परीक्षा और व्यावहारिक परीक्षण/साक्षात्कार दोनों को सफलतापूर्वक पूरा किया।

2.1. याचिकाकर्ता, एक भूतपूर्व सैन्यकर्मी की संतान होने के नाते, आरक्षण नियमों के तहत प्राथमिकता पर विचार करने का हकदार था। इस तरह के विचार का अनुरोध करने वाला एक पत्र सैनिक कल्याण बोर्ड विभाग को भेजा गया था। इसके अतिरिक्त, याचिकाकर्ता के पास औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में डिप्लोमा और राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद से राष्ट्रीय ट्रेड प्रमाणपत्र सहित सभी आवश्यक शैक्षणिक योग्यताएं थीं।

2.2. याचिकाकर्ता द्वारा प्रतिवादी संख्या 2 को नोटिस भेजने सहित अनेक प्रयासों के बावजूद जूनियर प्रशिक्षक पद पर उनकी नियुक्ति के संबंध में कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। इसलिए यह याचिका।

3. जवाब में दिया गया बचाव यह है कि याचिकाकर्ता व्यावहारिक परीक्षाओं के साथ-साथ साक्षात्कार में भी अनुत्तीर्ण हो गया। वास्तव में, इस तथ्य के बावजूद कि याचिकाकर्ता भर्ती नियमों के तहत निर्धारित मानदंडों के अनुसार नियुक्ति प्राप्त करने में विफल रहा, उसने केवल रिक्त पड़े बैकलॉग पदों के आधार पर नियुक्ति का दावा किया। इसलिए याचिका खारिज करने योग्य है।

4. उपर्युक्त पृष्ठभूमि में, मैंने याचिकाकर्ता के विद्वान वकील को सुना है और केस रिकॉर्ड का अध्ययन किया है। मैं याचिकाकर्ता के विद्वान वकील द्वारा दी गई निरर्थक दलीलों से खुद को यह समझाने में असमर्थ हूं कि इलेक्ट्रीशियन के पद के लिए व्यावहारिक परीक्षा और/या साक्षात्कार की कोई आवश्यकता नहीं है। याचिकाकर्ता के विद्वान वकील के तर्कों को इस हद तक बढ़ा-चढ़ाकर स्वीकार करना कि साक्षात्कार की कोई खास भूमिका नहीं है, लेकिन यह सुझाव देना कि एक इलेक्ट्रीशियन को अपने व्यावहारिक काम के बारे में नहीं पता होना चाहिए, पूरी तरह से बेतुका है।

5. इसके अलावा, याचिकाकर्ता का मामला ऐसा नहीं है कि उसे ही एकमात्र व्यक्ति था जिसे व्यावहारिक और साक्षात्कार दोनों की परीक्षा से गुजरने के लिए कहा गया था। उक्त मानदंड सभी उम्मीदवारों के लिए समान रूप से अपनाया गया था, और उन्हें व्यावहारिक और साक्षात्कार दोनों के लिए परीक्षण किया गया था। याचिकाकर्ता के तर्कों को स्वीकार करना कि कोई व्यावहारिक परीक्षा या साक्षात्कार नहीं होना चाहिए था, क्योंकि विज्ञापन

में इसकी परिकल्पना नहीं की गई थी, उसे दूसरों पर अनुचित लाभ देने के बराबर होगा जो व्यावहारिक परीक्षा में भी असफल हो सकते हैं, जैसा कि याचिकाकर्ता के मामले में है।

6. विदा लेते समय, मैं यह भी जोड़ना चाहूंगा कि मामले का एक और पहलू है यानी इस स्तर पर याचिकाकर्ता की योग्यता का पता लगाने के लिए चयन प्रक्रिया के रिकॉर्ड की कमी। चुनौती के तहत चयन प्रक्रिया वर्ष 2007 से संबंधित है और सभी संभावनाओं में पिछले कुछ वर्षों में इसका रिकॉर्ड नष्ट हो गया होगा।

7. प्रासंगिक चयन रिकॉर्ड की अनुपस्थिति में, याचिकाकर्ता का यह दावा कि वह जिस श्रेणी में आवेदन किया था, उसमें अंतिम चयनित उम्मीदवार से अधिक मेधावी है, पर विचार नहीं किया जा सकता। इसके अलावा, यहां तक कि अंतिम चयनित उम्मीदवार, जिसे याचिकाकर्ता के दावे को स्वीकार किए जाने की स्थिति में याचिकाकर्ता के लिए रास्ता बनाना होगा, को भी वर्तमान कार्यवाही में नामित या पक्ष नहीं बनाया गया है।

8. यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि प्रासंगिक श्रेणी में अंतिम चयनित उम्मीदवार इन सभी वर्षों से विचाराधीन पद पर काम कर रहा है और इस स्तर पर, इक्विटी उसके पक्ष में भारी है।

9. याचिकाकर्ता का यह भी दावा है कि उसके पिता एक पूर्व सैन्यकर्मी थे और वह आरक्षण के नियमों और विनियमों के अनुसार उपरोक्त पद के लिए प्राथमिकता दिए जाने के पात्र हैं। प्रतिवादियों का विशेष रुख यह है कि भर्ती नियमों के तहत भूतपूर्व सैन्यकर्मियों को आरक्षण देने का कोई प्रावधान नहीं है और यह जानकारी प्रतिवादियों ने सैनिक कल्याण बोर्ड, जयपुर को दिनांक 01.08.2007 के पत्र के माध्यम से दी थी। यह विवादित नहीं है कि प्रासंगिक भर्ती नियमों के तहत भूतपूर्व सैन्यकर्मियों या उनके आश्रितों के लिए आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है। याचिकाकर्ता को प्राथमिकता या अधिमान्यता देने का प्रश्न तभी उठ सकता है/उठेगा जब उसकी योग्यता अंतिम चयनित अभ्यर्थी के बराबर हो। वर्तमान मामले में ऐसी कोई स्थिति विद्यमान नहीं दिखाई गई है।

10. परिणामस्वरूप, ऊपर उल्लिखित सभी बिंदुओं पर याचिका में कोई योग्यता नहीं है, तदनुसार इसे खारिज किया जाता है।

11. लंबित आवेदन, यदि कोई हो, का निपटारा किया जाता है।

(अरुण मोंगा**),** न्यायाधीश

(यह अनुवाद एआई टूल: SUVAS की सहायता से किया गया है)

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के लिए सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।